D. Fisheries & Fish Processing.

1. Assistance for participation in deep sea fishing and processing.
2. Grant-in-aid providing interest subsidy on loan for acquisition of deep sea fishing vessel.
3. Assistance for diversified fishing.
4. Scheme for effective implementation of MZI Act by providing funds for installation of communication facilities for the Coast Guard.
5. Scheme for setting up of cold-chain.
6. scheme for tuna and other fish processing.
7. assistance to National Marine Fisheries Development Board.
8. Fishery Survey of India.

E. Consumer Industry.

1. R & D scheme on soyabean products and Indian traditional foods and packaging.
2. Investment in Public Sector Enterprises.
   a) MFIL
   b) NERAMAC

F. Secretariat Economic Services.

1. Scheme for strengthening of nodal agencies.
2. Scheme for strengthening of Directorate of F&VP for information, training, education and quality system for development of F&VP.
3. Scheme for participation in National and international exhibitions.
4. Scheme for promoting studies in food processing.
5. Scheme for performance awards in Food Processing Industries.

Introduction of Beer Parlour in Delhi

1037. DR. SANJAYA SINGH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the Government of the National Capital Territory of Delhi (NCT) have a proposal to introduce Beer Parlour in the Capital; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) and (b) A proposal has been initiated in this matter but the competent authority is yet to take a view in this regard.

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1038. श्री राम नरेश यादव: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) इन प्रस्तावों को स्वीकृति दिये जाने में कितना समय लगने की संभावना है और पिछले वर्ष कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन उद्योगों को कितनी सहायता दिये जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मांस प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के 3 प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इनमें (क) अलीगढ़ में एक पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना (ख) उत्तर प्रदेश में एक मांस परिसर की स्थापना और (ग) अलीगढ़ में एक आधुनिक सुअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना शामिल है। अलीगढ़ में आधुनिक सुअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र के लिये 1991-92 के दौरान 63 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा पेय अल्कोहल तैयार करने के 2 प्रस्तावों और बियर तैयार कर के 2 प्रस्तावों के लिये भी आशय-पत्र जारी किये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3 प्रस्तावों के लिये योजना सहायता मांगी गई है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं—नोडल एजेंसी को सुदृढ़ करना, डिब्बाबन्दी केन्द्रों के उन्नयन और खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना। इन सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।